

भीम प्रज्ञा अलर्ट

‘जिस समाज में दिखावे की आवाज़ सच से ऊँची हो जाती है, वहाँ इंसान धीरे-धीरे रिश्तों से नहीं, बल्कि अपने ही विवेक से दूर होने लगता है।’

सम्यक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एवं सामाजिक चेतना के लिए रचनात्मक पत्रकारिता

2009 से स्थापित

गांव के युवाइ से निकलकर प्रकाशित होने वाले दैनिक अखबार भीम प्रज्ञा की मजबूती के लिए पाठक बनिए और बनाइए अपनी प्रतिक्रिया दीजिए

हेल्पलाइन - 9983040937

Bheem Pragya publication

A/C No: 61347330768

IFSC Code- SBIN0031880

Phone pe , G-pay

9983040937

www.bheempragya.in

वर्ष-1

अंक-205

झुंझुनू (राजस्थान)

गुरुवार, 18 जून, 2026

Email.bheempragya@gmail.com

पृष्ठ-8

मूल्य: 5.00

सम्पादकीय



एडवोकेट
हरेश पंवार

Contact No.
9983040937

मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है

‘भाषणों में विश्वगुरु, जमीन पर आर्थिक मजबूरी : क्या हमारी विदेश नीति और आर्थिक प्रबंधन सवालों के घेरे में हैं?’

भारत आज वैश्विक मंचों पर स्वयं को एक उभरती हुई महाशक्ति और ‘विश्वगुरु’ के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत की विदेश नीति की सफलता के दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब यूक्रेन-रूस युद्ध जैसे क्षेत्रीय संघर्ष का असर भारत की आम जनता की रसोई, जेब और जीवनशैली पर सीधा दिखाई देने लगे, तो यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या हमारी आर्थिक और विदेश नीति वास्तव में उतनी मजबूत है, जितना उसका प्रचार किया जाता है? यहां मैं बोलूंगा तो फिर कहोगे कि बोलता है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अस्थिरता, रसोई गैस के बढ़ते दाम, खाद्य पदार्थों की महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये की लगातार कमजोर होती स्थिति ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि सरकार स्वयं जनता से अपील कर रही है कि लोग सोना कम खरीदें, विदेश यात्राएं टालें, ईंधन की खपत घटाएं और पारंपरिक चूल्हों का उपयोग करें। यह संदेश कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि आर्थिक दबाव सरकार के स्तर पर गंभीर रूप से महसूस किया जा रहा है।

यह सवाल भी जनता के मन में उठता है कि यदि देश की विदेश नीति इतनी प्रभावशाली है, तो भारत की मुद्रा लगातार कमजोर क्यों हो रही है? डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरना केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक क्षमता और वैश्विक विश्वास का दर्पण भी होता है। जब भारत से छोटे और कमजोर देशों की मुद्राएं भी अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई देती हैं, तब आम नागरिक का चिंतित होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ओर विडंबना सामने आती है। चुनावों के दौरान महंगाई नियंत्रित दिखाई देती है, पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहते हैं और जनता को राहत का वातावरण महसूस कराया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, आर्थिक संकट और महंगाई की चर्चा तेज हो जाती है। इससे आमजन के मन में यह धारणा बनने लगती है कि आर्थिक नीतियों का संचालन दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की बजाय राजनीतिक सुविधाओं के आधार पर हो रहा है। कोरोना काल का उदाहरण भी जनता के मन में कई सवाल छोड़ गया। जब देश महामारी और लॉकडाउन जैसी त्रासदी से गुजर रहा था, उससे पहले बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और राजनीतिक कार्यक्रमों पर भारी खर्च किए गए। ‘नमस्ते ट्रंप’ जैसे आयोजनों में करोड़ों रुपये खर्च हुए। आज जब आर्थिक संकट की बात हो रही है, तब जनता यह पूछने का अधिकार रखती है कि क्या उस समय राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग अधिक विवेकपूर्ण ढंग से नहीं किया जा सकता था? विदेश यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय छवि निर्माण की राजनीति भी अब जनता की आलोचना के घेरे में है। जनता यह देख रही है कि जब देश में बेरोजगारी, महंगाई, पंचायत चुनावों में देरी, ग्रामीण अव्यवस्था और स्थानीय प्रशासनिक संकट गहराते जा रहे हैं, तब सत्ता का बड़ा हिस्सा प्रचार और विदेश यात्राओं में अधिक व्यस्त दिखाई देता है। लोकतंत्र केवल भाषणों और नारों से नहीं चलता, बल्कि जमीनी व्यवस्था की मजबूती से चलता है। ग्रामीण भारत की स्थिति इस समय सबसे अधिक चिंताजनक दिखाई देती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने से गांवों की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। चुनी हुई ग्राम सरकारों के अभाव में प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही कम हुई है और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ा है। गांवों की गलियों में गंदगी, पानी की समस्या, विकास कार्यों की धीमी गति और आमजन की परेशानियां यह संकेत देती हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत-स्थानीय स्वशासन-कमजोर हो रहा है।

हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को टेंशन देता है : राहुल गांधी

5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर 5 लाख करोड़ खर्च होता है, इतना 5 मंत्रालयों का बजट

भीम प्रज्ञा न्यूज

कोटा । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को स्टूडेंट्स से संवाद किया। कार्यक्रम ‘छात्रों की गुंज’ में राहुल ने कहा- ये कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं, छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। राहुल गांधी ने कहा- हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज (दबाव में) करता है। यह उन्हें स्ट्रेस (तनाव) देता है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को ऐसा (आत्महत्या जैसा) आत्मघाती कदम न उठाना पड़े।

राहुल गांधी ने कहा-पांच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपके परिवारों की जेब से उतना पैसा छीन लिया जाता है जितना पांच मंत्रालयों का बजट है। नीट, जेईई सहित 5 परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों की जेब से 5 लाख करोड़ चले जाते हैं।



राहुल गांधी की 4 बड़ी बातें....

- जेब खाली करने वाला सिस्टम:** राहुल गांधी ने कहा- देश का एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार के नाम पर सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की जेब से पैसा खींचने का काम कर रहा है।
- थोपे जाते हैं करियर विकल्प:** राहुल ने स्टूडेंट्स से पूछा कि वे आईआईटी, मेडिकल, एसएससी या यूपीएससी ही क्यों चुनना चाहते हैं? इस पर छात्रों ने कहा कि बचपन से उन्हें यही बोला जाता है। अगर उन्हें मन की करने दी जाए, तो कोई डॉक्टर तो कोई पायलट बनना चाहता है।
- युवाओं के पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन क्यों:** राहुल गांधी ने कहा-देश के युवाओं के पास एजुकेशन में सिर्फ पांच ही ऑप्शन क्यों हैं? हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनना चाहता है, जबकि और भी कई करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने एक छात्रा का सुसाइड नोट दिखाया और कहा- यह आकांक्षा का फेल्ट्योर नहीं है, बल्कि यह हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेल्ट्योर है।
- मनपसंद स्ट्रीम चुनने की हो आजादी:** राहुल ने कहा- एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे और युवा अपने मन की चीज कर सकें, अपनी पसंद की स्ट्रीम चुन सकें और उसकी तैयारी में लाखों रुपये का भारी-भरकम खर्च न हो।



राहुल गांधी ने कहा- यह सिर्फ पैसे वसूलने का सिस्टम है

राहुल गांधी ने कहा- यह सिस्टम सिर्फ पैसे वसूलने का सिस्टम बन चुका है। एक हजार लोगों में से केवल 12 को रोजगार मिलता है, बाकी लोग क्या करेंगे? कोई कुली बनेगा, तो कोई ओला-उबर चलाएगा। हिंदुस्तान में आज 100 में से 80 इंजीनियर बेरोजगार हैं।

आज मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूँ। हमें इस सिस्टम को बदलना और ठीक करना होगा। एजुकेशन सिस्टम वह होता है जिसमें आप बड़े से बड़ा सपना देख सकें और उसे कम खर्च पर पूरा कर सकें।

खेतड़ी उप जिला अस्पताल में ट्रोमा सेंटर के पद स्वीकृत



16 नए पद सृजित, आमजन को मिलेगी बेहतर सुविधा

भीम प्रज्ञा न्यूज

खेतड़ी । राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने खेतड़ी उप जिला अस्पताल में प्रस्तावित ट्रोमा सेंटर के संचालन के लिए विभिन्न पदों को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध होगा।

ट्रोमा सेंटर के लिए 16 नए पद सृजित

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ट्रोमा सेंटर के लिए कुल 16 नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें एक कनिष्ठ विशेष सर्जरी, दो चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर सर्जरी), तीन चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर

हृद्) और दस नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों से ट्रोमा सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

जरूरी उपकरण की खरीद के लिए बजट स्वीकृत

बीसीएमओ डॉ. हरश्री यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने ट्रोमा सेंटर के भवन निर्माण और आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए भी बजट स्वीकृत किया है। इससे आधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रोमा सेंटर विकसित किया जा सकेगा। वर्तमान में गंभीर रूप से घायल मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करना पड़ता है, लेकिन ट्रोमा सेंटर शुरू होने के बाद कई मामलों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही संभव हो पाएगा। क्षेत्र के लोग लंबे समय से खेतड़ी में ट्रोमा सेंटर की मांग कर रहे थे। पदों की स्वीकृति मिलने से आमजन में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं, औद्योगिक हादसों और अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिलेगी, जिससे जीवन बचाने में मदद मिलेगी।

जसरापुर जीएसएस का ट्रांसफार्मर जला, 28 घंटे से बिजली ठप

पांच फीड्स में आपूर्ति बाधित, ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर बहाली की मांग की

भीम प्रज्ञा न्यूज

जसरापुर (खेतड़ी) । जसरापुर जीएसएस पर लगा 3.15 एमवीए क्षमता का मुख्य विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने से जसरापुर सहित पांच फीड्स की बिजली आपूर्ति पिछले 28 घंटों से ठप पड़ी है। भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण जसरापुर, पावटा, श्यामपुर, रामा की ढाणी, छाबड़िया वाला तथा माताजी की ढाणी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। लगातार बिजली गुल रहने से घरों में पंखे, कुलर और अन्य विद्युत उपकरण बंद पड़े हैं। भीषण गर्मी के कारण लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है, जिससे छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष परेशानी हो रही है।

पानी की समस्या गहराई

पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होने से पानी की समस्या गहरा



गई है, वहीं किसानों के सिंचाई कार्य भी रुक गए हैं। ई-मित्र संचालक राजेश जलन्दा ने बताया कि बिजली नहीं होने के कारण ई-मित्र केंद्रों पर विभिन्न सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों एवं अन्य ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े कार्य ठप पड़े हैं, जिससे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मोबाइल चार्जिंग और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

नकली बीज घोटाले पर कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग, किसान महासभा चलाएगी जनजागरण अभियान

भीम प्रज्ञा न्यूज.चिड़ावा।

अखिल भारतीय किसान महासभा की जिला कमिटी की बैठक बुधवार को चिड़ावा स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष कामरेड ओमप्रकाश झारोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत राज्य उपाध्यक्ष कामरेड रामस्वरूप मणकश एवं भगवान सिंह कोझाण के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड फूलचंद देवा ने केंद्र सरकार की भारत-अमेरिका ट्रेड डील और राज्य सरकार की कृषि नीतियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री की शह पर विभाग के उच्च अधिकारी करोड़ों रुपये के नकली बीज घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं और मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रीय सचिव कामरेड रामचंद्र कुलहर ने कहा कि खेती और किसानों को कॉर्पोरेट लूट से बचाने के लिए गांव-गांव में किसान समितियों का गठन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 20 जून से 20 जुलाई तक जिलेभर में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। 20 जून से 4 जुलाई तक जनसंपर्क और पर्याप्त वितरण किया



जाएगा, जबकि 5 जुलाई से 20 जुलाई तक पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा की शुरुआत चरणसिंह नगर से होगी और खेतड़ी, चिड़ावा, सिंघाना तथा बुहाना क्षेत्र से होते हुए 20 जुलाई को संपन्न होगी। दूसरे चरण में सूरजगढ़, पिलानी, चिड़ावा और झुंझुनू प्रखंडों में भी पदयात्रा अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इनमें भारत-अमेरिका कृषि डील को रद्द करने, एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य, नकली बीज घोटाले की न्यायिक जांच, यमुना नहर का पानी शीघ्र लाने, स्मार्ट मीटर योजना बंद करने,

सड़क एवं बिजली परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने तथा मंदिर माफी भूमि पर खातेदारी अधिकार देने जैसी मांगें शामिल हैं। बैठक को जिला उपाध्यक्ष कामरेड इंद्राज सिंह चारावास, चिड़ावा प्रखंड सचिव रामोतार शर्मा, सिंघाना प्रखंड अध्यक्ष विद्याधर गर्सा, सूरजगढ़ प्रखंड अध्यक्ष जयपाल सिंह बसेरा, रीतास काजला, प्रेम सिंह नेहरा, मनफूल सिंह, शीशराम गोठवाल, वीरभान, रत्तीराम राव तथा पिलानी प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र सिंह कुलहर सहित अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। महासभा ने जिलेभर में 10 हजार सदस्य बनाने और ग्राम स्तर पर समितियों के गठन का भी लक्ष्य निर्धारित किया है।

पंचायती राज कर्मचारी 19 को करेंगे सद्बुद्धि यज्ञ:जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन का निर्णय

बैठक में कर्मचारियों को मांगों की जानकारी दी

भीम प्रज्ञा न्यूज

उदयपुरवाटी । पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 19 तारीख को जिला मुख्यालय पर सद्बुद्धि यज्ञ करने का निर्णय लिया है। यह फैसला बुधवार को उदयपुरवाटी पंचायत समिति सभागार में आयोजित संगठन की जिला स्तरीय बैठक में लिया गया। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रमोद चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला मुख्यालय पर प्रस्तावित सद्बुद्धि यज्ञ के आयोजन पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के तहत इस कार्यक्रम को करने का निश्चय किया है।



उदयपुरवाटी ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह फोजी ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में जानकारी दी। जिला परिषद से आए ओमप्रकाश झाड़ाड़िया, सुरेंद्र वर्मा और अनिल सिहाग ने कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान पर बात की। पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश बराला ने संगठन के

मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की।

ये रहे मौजूद

बैठक में ब्लॉक महामंत्री अशोक रेगर, जिला उपाध्यक्ष जयसिंह आलडिया, ब्लॉक उपाध्यक्ष अनिल महला, पूर्णमल जाट, सुभिता, सजना, इंद्रा सहित रामस्वरूप चौहान, मुकेश कुमार सेनी, अभिषेक, कमलेश ओला, छोटा राम मीणा, कुलदीप सिंह, पुरुषोत्तम स्वामी, सुनीता, रेनु आलडिया, सोनिया भारती, ज्योति, विशोरी लाल जांगिड़, रामवतार जांगिड़, तिलक राज और महेश चंद्र जैसे कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

पूर्व पालिकाध्यक्ष सुभाष शर्मा के बड़े भाई नगेन्द्र शर्मा का निधन, 19 जून को श्रद्धांजलि सभा

भीम प्रज्ञा न्यूज.चिड़ावा

चिड़ावा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सुभाष शर्मा के बड़े भाई नगेन्द्र शर्मा



(71) का 11 जून को मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से चिड़ावा सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्वर्गीय नगेन्द्र शर्मा अपने पिछे पत्नी और दो पुत्रों सहित भ्राता-पुत्रा परिवार छोड़ गए हैं। पारिवारिक सुत्रों के अनुसार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 19 जून को श्रद्धांजलि सभा (शोक बैठक) का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सूरजगढ़ रोड स्थित मधुसूदन फार्म हाउस में शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। श्रद्धांजलि सभा में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी तथा शुभचिंतक उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे।



बजट में ट्रिप प्लान करने के लिए जरूरी है कि आप सही लोकेशन का चुनाव करें

सिंगल मदर्स के लिए बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं होता है। क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसी कई परेशानियां आती हैं, जिन्हें वह अकेले मैनेज करती हैं। लेकिन सिंगल मदर्स अपने बच्चे को हर खुशी देने की कोशिश करती हैं। इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे घूमने जाने की जिद करते हैं। ऐसे में मां अपने बच्चे के लिए भी ट्रिप प्लान करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वह कम बजट में ट्रिप कैसे प्लान करें। क्योंकि उन्हें अकेले ही घर और बाहर सब मैनेज करना होता है। वहीं अगर आप भी सिंगल मदर हैं और बजट में ट्रिप प्लान करने में परेशान हो रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे हेक्स बताते जा रहे हैं,

जिनको फॉलो करके आप सिर्फ 10 हजार रुपए में घूमने का प्लान बना सकती हैं।

ऐसे प्लान करें ट्रिप

बजट में ट्रिप प्लान करने के लिए जरूरी है कि आप सही लोकेशन का चुनाव करें। क्योंकि सही लोकेशन आपके बजट को कम करती है। भले ही आप इन जगहों पर घूम चुकी हों, लेकिन बच्चे के लिए आप किसी सस्ती जगह का चुनाव कर सकती हैं।

वहीं सिंगल मदर्स को ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए, जहां पर अच्छी सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक हो। जहां पर सस्ते ऑटो या कैब आदि आसानी से मिल सकें। जैसे पहाड़ों वाली जगह पर हर

चीज का दाम अधिक रहता है। इन जगहों पर खाने-पीने से लेकर स्टे तक के साधन काफी महंगे होते हैं।

वहीं आपको अपने साथ कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें रखनी चाहिए, जो जल्दी खराब न हों। ट्रिप के दौरान आप साथ में फल लेकर जा सकती हैं। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जल्दी भूख भी नहीं लगेगी।

बजट में घूमने के लिहाज से दूर पैकेज बेस्ट ऑप्शन होते हैं

सही लोकेशन का चुनाव करने पर आपको होटल भी कम दाम में मिल जाते हैं और यहां पर पहुंचना भी आसान होता है।

अधिकतर सिंगल मदर्स शहर से बाहर नहीं जाना चाहती हैं, तो आप शहर में रहकर भी घूमने जाने का प्लान बना सकती हैं। आप शहर में बच्चे को ऐसी जगह घुमाएं, जहां पर बच्चे हमेशा से जाना चाहते थे। ऐसा करने से न सिर्फ ट्रेवल और होटल का खर्चा बचेगा, बल्कि शहर में रहकर बच्चे अपनी पसंदीदा जगह घूम सकेंगे।

दूसरे शहर में कम खर्च के लिहाज से आप शेयरिंग के साधन से घूम सकती हैं। क्योंकि इसमें कम बजट होता है। वहीं बच्चों के साथ घूमने के लिए यह टिप्स आपकी यात्रा को आसान बना देगी।



देहरादून में करना चाहते कुछ तूफानी तो जरूर एक्सप्लोर करें ये जगहें, जमकर कर सकेंगे मस्ती

देहरादून एक ऐसी जगह है, जहां पर आपको खूबसूरत हिल स्टेशन मिलेंगे। यहां से हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और धनोल्डी जैसी कई जगहों पर आप जा सकते हैं। वहीं अगर आप देहरादून में कुछ रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं। वहीं कुछ देहरादून में ऐसी जगहों की तलाश करना चाहते हैं, जहां पर कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकें। अगर आप भी देहरादून में कुछ तूफानी करना चाहते हैं, तो आपको आसपास के हिल स्टेशन पर घूमने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देहरादून की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में बताते जा रहे हैं।

रॉबर्स केव देहरादून
देहरादून की यह आपको काफी रोमांचक लगेगी। क्योंकि इसकी बनावट लोगों को



आकर्षित करती है। जिन लोगों ने

पहले कभी गुफा वाली जगहों पर प्रवेश नहीं किया है, उनके लिए यह एडवेंचर्स साबित हो सकता है। क्योंकि यहां पर आपको पैदल जाना होगा। पैरों में पानी होता है और मछलियां आपके पैरों को छूती हैं। हालांकि शुरुआत में आपको गुफा में चलने में थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे अंदर जाते ही नॉर्मल लगने लगेगा। प्रयास करें कि आप सुबह-सुबह पहुंचें, क्योंकि यहां पर बहुत भीड़ लगती है। यह मसूरी के पास घूमने लायक अच्छी जगहों में से एक है।

रॉक क्लाइंबिंग

अगर आप कुछ तूफानी करना चाहते हैं और बिना किसी सहाय के पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं। तो आपको देहरादून में रॉक क्लाइंबिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। यह सालाना गांव में रॉक क्लाइंबिंग करवाई जाती है। जहां पर आपको

हर दिन भीड़ देखने को मिलेगी। आप यहां पर कैपिंग के साथ कई तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। वहीं आप यहां पर पैकेज भी बुक कर सकते हैं और पूरा रात टेंट में बिता सकते हैं। इस दौरान आपको मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना होगा और पूरी लाइफ कैप की तरह जीना होगा। यह आपके लिए एक रोमांचक अनुभव हो सकता है।

मालसी डियर पार्क

अगर आप देहरादून में कुछ रोमांचक करना चाहते हैं, तो मालसी डियर पार्क जा सकते हैं। क्योंकि यह जगह आपको निराश नहीं करेगी। आप यहां पर जिप लाइनिंग और तरह-तरह की एक्टिविटी भी कर सकेंगे। बच्चों को भी यहां पर एक्टिविटी करवाई जाती है। वहीं अगर आप छोटा ट्रिप प्लान कर रही हैं, तो आपको यहां पर आपको भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। यह देहरादून के पास घूमने वाली बेस्ट जगहों में से एक है।

भीड़ से दूर बेहद शांत है उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन, जन्मत में आने का होगा एहसास

समर वेकेशन में हजारों लोग घूमने-फिरने के लिए निकल गए हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रिप प्लान नहीं कर पाए हैं। वह किसी पहाड़ी जगह पर घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऋषिकेश-नैनीताल नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इन जगहों पर समर वेकेशन में यहां पर पर्यटकों की अधिक भीड़ आती है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं, जो नैनीताल और ऋषिकेश से भी अधिक सुंदर हो। तो आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको उत्तराखंड की एक सबसे खूबसूरत जगह के बारे में बताते जा रहे हैं।

मुनस्वारी – अगर आप भी दिल्ली की गर्मी से परेशान होकर अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। तो फौरन आपको मुनस्वारी का ट्रिप प्लान करें। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, ट्रेकिंग और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है। मुनस्वारी में गर्मियों में आपको अधिक भीड़ नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मुनस्वारी काफी ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल से मुनस्वारी पहुंचने में आपको करीब 11 से 12 घंटे का समय लगता है। वहीं ऋषिकेश से भी यहां तक पहुंचने में करीब इतना ही समय लगेगा। यह मसूरी के पास घूमने के लिहाज से काफी अच्छी जगह है।

ऐसे पहुंचें मुनस्वारी

अगर आप दिल्ली से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो बस से यात्रा करने के लिए अच्छा है। हालांकि इसमें ज्यादा समय लग सकता है।

अगर आप चाहें तो दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन ले सकते हैं। फिर मुनस्वारी के लिए बस ले सकते हैं।

इसके साथ ही मुनस्वारी के लिए कैब की सुविधा भी मौजूद है। लेकिन इसमें खर्च ज्यादा होता है। वहीं अगर आप बजट में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो बस से यात्रा करें।

आने-जाने में असुविधा न हो इसके लिए पहले से बस की बुकिंग कर लें। क्योंकि अधिक भीड़ होने पर आपको बस में सीट मिलने में मुश्किल हो सकती है।

दिल्ली से मुनस्वारी की दूरी करीब 604 किमी है। यहां पर पहुंचने में आपको 13-14 घंटे का समय लग सकता है।

प्रयास करें कि आप रात में बस ले लें। जिससे कि सुबह मुनस्वारी में ही आंख खोलें। इससे आपका सफर आराम से सोकर बीतेगा।

मुनस्वारी परिवार के साथ घूमने के लिहाज से काफी अच्छी जगह है।

प्रकृति, शांति और रोमांच का संगम है पार्वती घाटी में बसा कसोल

हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा कसोल एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो खासकर युवाओं, ट्रेकिंग प्रेमियों और विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। समुद्र तल से लगभग 1,580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कसोल को फ़ भारत का मिनी इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में इजराइली पर्यटक आते हैं और यहाँ की संस्कृति में उनका प्रभाव देखा जा सकता है।

कसोल की खासियत

कसोल एक शांत और सुरम्य गाँव है, जो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, स्वच्छ और ठंडा होता है। ऊँचे पहाड़, घने देवदार के जंगल, कलकल बहती पार्वती नदी और रंग-बिरंगे कैफ़े इस स्थान को बेहद आकर्षक बनाते हैं।



प्रमुख आकर्षण

1. पार्वती नदी

यह तेज बहाव वाली नदी कसोल की जान मानी जाती है। इसके किनारे टहलना, चट्टानों पर बैठकर मन को शांति देना और फोटोग्राफी करना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है।

2. तोश और मणिकरण

कसोल से थोड़ी दूरी पर स्थित ये गाँव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। मणिकरण में गर्म पानी के झरने और गुरुद्वारा प्रमुख आकर्षण हैं, जबकि तोश ट्रेकिंग प्रेमियों का पसंदीदा गाँव है।

3. चालल गाँव

कसोल से लगभग 30 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित यह छोटा गाँव ट्रेकिंग और कैम्पिंग के लिए आदर्श है। यहाँ आप स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

4. इजराइली कैफ़े और भोजन

कसोल में कई इजराइली कैफ़े और रेस्तराँ हैं जहाँ आप फलाफल, शाकशुका, हुम्मस आदि विदेशी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

कसोल में करने योग्य गतिविधियाँ

ट्रेकिंग (खीरगंगा, तोश, चालल, ग्रहन)
कैम्पिंग और बोनफायर
रिवर साइड कैफ़े में समय बिताना
स्थानीय लोगों से मिलकर पहाड़ी संस्कृति को समझना

हर्बल चाय और हिमाचली हस्तशिल्प की खरीदारी

यात्रा का उत्तम समय
मार्च से जून- गर्मियों में ठंडी जलवायु और ट्रेकिंग के लिए अनुकूल मौसम।

सितंबर से नवंबर- मानसून के बाद की हरियाली और साफ़ आसमान।
दिसंबर से फरवरी- बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तम।

कैसे पहुँचें कसोल?

हवाई मार्ग- निकटतम हवाई अड्डा भुंतर (कुल्लू) है, जो कसोल से लगभग 31 किमी दूर है।

रेल मार्ग- निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर है, लेकिन सड़क मार्ग से पहुँचना अधिक सुविधाजनक है।

सड़क मार्ग- दिल्ली, चंडीगढ़ और मनाली से कसोल तक नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं।

कसोल एक ऐसा गंतव्य है जहाँ आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। यहाँ का शांत वातावरण, रोमांचक ट्रेक्स, विदेशी भोजन और पहाड़ी सौंदर्य, हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देता है। चाहे आप सोलो ट्रेवलर हों, कपल या दोस्तों के साथ – कसोल हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव है।

सीकर । सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने नीट पेपरलोक के विरोध में बुधवार को आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च डाक बंगला परिसर से शुरू होकर नवलगढ़ पुलिया होते हुए सीएलसी चौराहे पर पहुंचा। आक्रोश मार्च के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा- जब से NTA का गठन हुआ है, तब से लेकर आज तक वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, बल्कि नेशनल टॉरर एजेंसी है। उन्होंने कहा- 10 साल में NTA के 89 पेपरलोक हुए हैं। 46 बार दोबारा एग्जाम हुई। उन्होंने कहा- SFI अब 19 जून को नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का घेराव करेगी। वहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक स्टूडेंट्स वहीं बैठ रहेंगे। जाखड़ ने कहा- नीट का पेपर रद्द होने के बाद सीकर में प्रदीप मेघवाल और उमेश माली ने सुसाइड कर लिया। इन दोनों की मौत का जिम्मेदार देश की सरकार है, लेकिन शिक्षा मंत्री एक शब्द भी नहीं बोल रहे।



गुजरात की नई औद्योगिक नीति का ऐलान, 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

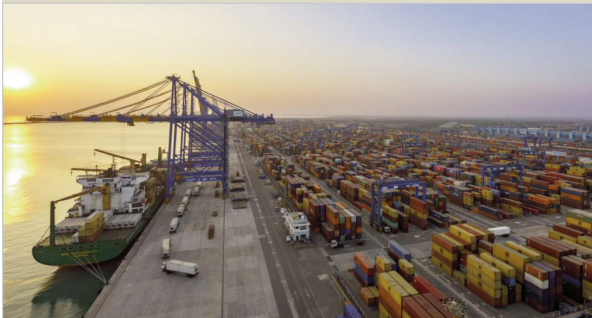
मुख्यमंत्री ने विकसित गुजरात औद्योगिक नीति-2026 का अनावरण किया

गांधीनगर ।

गुजरात सरकार ने अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ अपनी नई औद्योगिक नीति 'विकसित गुजरात औद्योगिक नीति-2026' की घोषणा की है। यह नीति आगामी पांच वर्षों के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्नत विनिर्माण, नवाचार और स्टार्टअप के लिए एक मजबूत एवं सहयोगी ढांचा विकसित करना है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 15 से 50 फीसदी तक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में इस नीति का अनावरण किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, मुख्य सचिव एम. के. दास सहित अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। यह दूरगामी नीति वर्ष 2047 तक गुजरात को 3.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में राज्य की प्रगति को गति देने और उन्नत विनिर्माण व नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

मई में भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर, व्यापार घाटा बरकरार

पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों ने दी रफ्तार; आयात में भी तेज वृद्धि दर्ज



नई दिल्ली ।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई माह में भारत के व्यापारिक वस्तु निर्यात ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। यह 45.20 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, इस दौरान आयात में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश का व्यापार घाटा ऊंचा बना रहा। आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोलियम उत्पादों और इंजीनियरिंग वस्तुओं के मजबूत प्रदर्शन ने निर्यात वृद्धि में अहम योगदान दिया। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 55 प्रतिशत बढ़कर 8.42 अरब डॉलर हो गया, जबकि इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर 12.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य अ धिकारी ने बताया कि पश्चिम एशिया को होने वाला निर्यात मई में 5.30 अरब डॉलर रहा, जो लगभग मई 2025 के स्तर पर लौट आया है। यह शिपिंग मंत्रालय और निर्यात संवर्धन एजेंसियों के प्रयासों से संभव हुआ, जिन्होंने होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के दौरान वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की। दूसरी ओर, देश का आयात भी लगभग 21 प्रतिशत बढ़कर 73.41 अरब डॉलर के पिछले साल महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मासिक आयात बिल है, जो पिछले वर्ष अक्टूबर के 76.73 अरब डॉलर के रिकॉर्ड से कुछ कम है। इसके परिणामस्वरूप, मई में व्यापार घाटा 28.21 अरब डॉलर रहा, जो अप्रैल के 28.38 अरब डॉलर से थोड़ा कम है लेकिन पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो मई में सेवाओं का निर्यात अनुमानित रूप से 13 प्रतिशत बढ़कर 36.76 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 14 प्रतिशत बढ़कर 19.06 अरब डॉलर हो गया। इससे सेवाओं के व्यापार में भारत को मई में लगभग 17.70 अरब डॉलर का अधिशेष मिला, जो एक सकारात्मक संकेत है। राजेश अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि अगर अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद पश्चिम एशिया में स्थिति सामान्य रहती है, तो जून में निर्यात और बेहतर रहने की संभावना है।

स्किल कोर्स 28 लाख ने किया,नौकरी मिली सिर्फ 23 फीसदी को!

प्रमाणन दर भी निराशाजनक, नीति-निर्माताओं की चिंता बढ़ी

नई दली ।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) अकादमी के अपने दो दिवसीय दौर के दौरान वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉंग से मुलाकात की और राज्य में तकनीकी सहयोग व निवेश की मांग की। उन्होंने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम मेधा (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग और विश्वविद्यालय शोध जैसे उभरते क्षेत्रों में साझेदारी पर

बड़ी चुनौती को दर्शाती है। 8 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक एनएसडीसी अकादमी के माध्यम से दाखिला लेने वाले 28.3 लाख उम्मीदवारों में से केवल 6,60,586 को ही नौकरी मिल पाई है, जो लगभग 23 प्रतिशत की रोजगार दर है।

इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि दाखिला लेने वालों में से आधे से भी कम (लगभग 14 लाख) उम्मीदवारों की ही प्रमाणपत्र मिल पाए, जो दाखिले के बाद प्रमाणन और फिर नौकरी तक पहुंचने की प्रक्रिया में एक

विशेष जोर दिया। बैठक में नायडू ने सिंगापुर से आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने व क्षमता निर्माण में मदद मांगी। उन्होंने उद्यम पूंजी और स्टार्टअप निवेशकों को राज्य में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया, साथ ही राज्य के बढ़ते औद्योगिक परिवेश, नवाचार अवसरंचना और निवेशक-



बड़े अंतर को उजागर करता है। वर्ष 2023 में शुरू हुई एनएसडीसी अकादमी का उद्देश्य उच्च शिक्षा के साथ उद्योग-जुड़े कौशल विकास को जोड़ना और रोजगार क्षमता बढ़ाना है। हालांकि, मौजूदा आंकड़े इस पहल की वास्तविक प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करते हैं। नीति-निर्माता अब केवल दाखिले की संख्या के

अनुकूल नीतियों को रेखांकित किया। उन्होंने औद्योगिक परियोजनाओं व रतन टाटा नवाचार के द्र के माध्यम से विकसित स्टार्टअप में निवेश का सही समय बताया। यात्रा के दौरान नायडू ने सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों व निवेशकों से मुलाकात कर अवसरंचना, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण व शिक्षा में निवेश पर चर्चा की। भारत के

बजाय रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने प्लेसमेंट को जोड़ना और रोजगार क्षमता बढ़ाना है। हालांकि, मौजूदा आंकड़े इस पहल का 'असली पैमाना' बताया है। ये आंकड़े सरकारी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने बताया कि सिंगापुर हरित ऊर्जा और सेमीकंडक्टर परिवेश में अग्रणी है तथा भारत के राज्यों के साथ काम करने को इच्छुक है। नायडू ने संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट और गूगल क्लाउड से साझेदारी का प्रस्ताव भी रखा, तथा सिंगापुर की कंपनियों को लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला व डिजिटल अवसरंचना में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

सिंगापुर में आंध्र प्रदेश के लिए तकनीकी-निवेश साझेदारी की वकालत

सेमीकंडक्टर, एआई और विश्वविद्यालय शोध में सहयोग पर जोर

नई दिल्ली ।

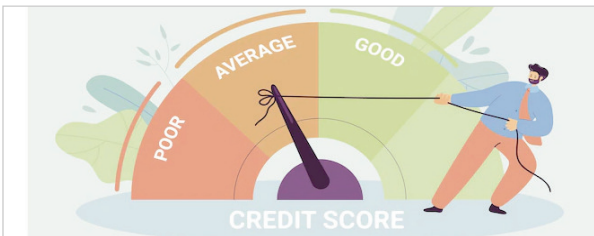
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के अपने दो दिवसीय दौर के दौरान वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉंग से मुलाकात की और राज्य में तकनीकी सहयोग व निवेश की मांग की। उन्होंने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम मेधा (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग और विश्वविद्यालय शोध जैसे उभरते क्षेत्रों में साझेदारी पर

क्रेडिट स्कोर के आधार पर महंगा हुआ कर्ज, उपभोक्ताओं पर बढ़ा बैंक ब्याज का बोझ

नई दिल्ली ।

बैंकों द्वारा ऋण में क्रेडिट स्कोर को अधिक महत्व दिए जाने के बाद कई उपभोक्ताओं को कर्ज लेना महंगा हो गया है। वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जानकारों के अनुसार अब अधिकांश बैंक और वित्तीय संस्थान उधारकर्ताओं के क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज की वसूली करेंगे। रिजर्व बैंक के नए आदेश से जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक ब्याज दें तय कर रहे हैं। बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले

ग्राहकों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर होगी। जबकि कम स्कोर वाले ग्राहकों से 2 से 2.5 प्रतिशत तक अधिक ब्याज बैंकों द्वारा वसूल किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है, जोखिम आधारित कर्ज निर्धारण कर पुराने कर्ज पर उपभोक्ताओं से ज्यादा रेट पर ब्याज की वसूली की जाएगी। उपभोक्ता संगठनों का तर्क है, इससे मध्यम वर्ग और पहली बार ऋण लेने वाले लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का तरीका नहीं है। जिसके



कारण रेटिंग खराब होती है। कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों की मासिक ईएमआई में बढ़ी वृद्धि हो सकती है। गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर इसका असर पड़ेगा। जिस तरह से

महंगाई बढ़ रही है। आमदनी घट रही है ऐसे समय पर रिजर्व बैंक ने गरीब और मध्यम वर्ग पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। जिससे लोगों में नाराजी फैल रही है।

कच्चे तेल में गिरावट से सरकारी तेल कंपनियों को बंपर फायदा

ब्रेंट के 65 डॉलर तक फिसलने का अनुमान

मुंबई ।

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट से देश की सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) को बड़ा फायदा मिल रहा है।

पेट्रोल और डीजल की हालिया मूल्य वृद्धि के साथ कच्चे तेल के नरम पड़ने से कंपनियों की कमाई में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड 125 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर था, जो अब घटकर करीब 83 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। इस नरमी से तेल कंपनियों पर दबाव कम हुआ है और वे ऑटो फ्यूल कारोबार में सामान्य मुनाफे के



करीब पहुंच चुकी हैं। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और पिछले एक महीने में ओएमसी शेयरों में अच्छी तेजी भी देखी गई है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट के अनुसार ओएमसी के लिए हालात बेहतर दिख रहे हैं। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगले कुछ

सरकार जीआईसी में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी

नई दिल्ली ।

सरकार जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) में अपनी पांच प्रतिशत तक हिस्सेदारी 352 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचेगी।

मंगलवार से शुरू हुई इस दो दिवसीय बिक्री पेशकश (ओएफएस) से सरकारी खजाने को लगभग 3,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के एक अधिकारी ने बताया कि संस्थागत निवेशक मंगलवार को और खुदरा निवेशक बुधवार को बोली लगा सकेंगे।

सरकार प्रारंभिक दो प्रतिशत इक्विटी के साथ, ग्रीन शू विकल्प के तहत अतिरिक्त तीन प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेचेगी। यह न्यूनतम कीमत सोमवार के बंद भाव (388.35 रुपये) से 9.36 प्रतिशत कम है। चालू वित्त वर्ष में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचकर अब तक 13,389 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

लीपफॉग इंजीनियरिंग का आईपीओ 17 जून को खुलेगा

मुंबई ।

बेंगलुरु स्थित लीपीफॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ने अपने आर्थिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 21-23 प्रति शेयर निर्धारित किया है। कंपनी का 88.51 करोड़ का यह आईपीओ बुधवार को निवेशकों के लिए खुलेगा। यह आईपीओ सदस्यता के लिए बुधवार को खुलेगा और शुक्रवार को बंद होगा। इसमें 79.60 करोड़ रुपए के लगभग 3.46 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और 8.91 करोड़ रुपए के लगभग 38.75 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। कंपनी के शेयर बीएसई एएसई मंच पर सूचीबद्ध होंगे। लीपीफॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज एक इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और कमीशनिंग (ईपीसीसी) कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कंपनी ने अपनी मजबूत व्यावसायिक स्थिति का प्रदर्शन करते हुए 384 करोड़ रुपए से अधिक की ऑर्डर बुक बनाई है। इसमें 327 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर इसकी क्षमताओं को दर्शाती हैं।

लीपफॉग इंजीनियरिंग का आईपीओ 17 जून को खुलेगा

मुंबई ।

बेंगलुरु स्थित लीपीफॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ने अपने आर्थिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 21-23 प्रति शेयर निर्धारित किया है। कंपनी का 88.51 करोड़ का यह आईपीओ बुधवार को निवेशकों के लिए खुलेगा। यह आईपीओ सदस्यता के लिए बुधवार को खुलेगा और शुक्रवार को बंद होगा। इसमें 79.60 करोड़ रुपए के लगभग 3.46 करोड़ इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और 8.91 करोड़ रुपए के लगभग 38.75 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। कंपनी के शेयर बीएसई एएसई मंच पर सूचीबद्ध होंगे। लीपीफॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज एक इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और कमीशनिंग (ईपीसीसी) कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कंपनी ने अपनी मजबूत व्यावसायिक स्थिति का प्रदर्शन करते हुए 384 करोड़ रुपए से अधिक की ऑर्डर बुक बनाई है। इसमें 327 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर इसकी क्षमताओं को दर्शाती हैं।

बेरोजगारी ने तोड़ा 11 महीने का रिकॉर्ड, मई में 5.5 फीसदी पर पहुंची दर

श्रम बल भागीदारी में भी गिरावट, काम की तलाश करने वालों का अनुपात 54.4 फीसदी हुआ

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के नवीनतम मासिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के श्रम बाजार ने मई में एक चिंताजनक प्रवृत्ति प्रदर्शित की है, जिसमें बेरोजगारी दर (यूआर 11) महीने के उच्चतम स्तर 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह वृद्धि अप्रैल के 5.2 प्रतिशत से हुई है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि यह श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में गिरावट के बावजूद दर्ज की गई है, जो काम करने या काम की तलाश करने वाले लोगों के अनुपात में कमी का संकेत देती है। यह डेटा देश में रोजगार परिदृश्य की अंतर्निहित कमजोरी को उजागर करता है। आंकड़ों के मुताबिक मई में एलएफपीआर घटकर 54.4 प्रतिशत रह गई, जो पिछले 11 महीनों का सबसे निचला स्तर है, जबकि अप्रैल में यह 55 प्रतिशत थी। इसी तरह, रोजगार प्राप्त लोगों का अनुपात भी अप्रैल के 52.2 प्रतिशत से घटकर मई में 51.4 प्रतिशत पर आ गया, जो एक और 11 महीने का निचला स्तर है। एनएसओ के विश्लेषण के अनुसार कामकाजी आबादी और रोजगार प्राप्त लोगों के अनुपात में कमी तथा बेरोजगारी में वृद्धि से स्पष्ट होता है कि मई के दौरान श्रम

बाजार की स्थिति कमजोर हुई है। यह दर्शाता है कि रोजगार के अवसरों में गिरावट, काम की तलाश करने वालों की संख्या में कमी की तुलना में अधिक तेज रही है, जिससे कुल बेरोजगारों का अनुपात बढ़ गया है। आर्थिक गतिविधियों में मौसमी सुस्ती भी इसकी एक संभावित वजह मानी जा रही है। क्षेत्रीय और लिंग-विशिष्ट विश्लेषण से भी महत्वपूर्ण रुझान सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एलएफपीआर अप्रैल के 57.5 प्रतिशत से घटकर मई में 56.6 प्रतिशत रह गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह मामूली गिरावट के साथ 50.1 प्रतिशत से 49.8 प्रतिशत पर आई है। ग्रामीण बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो अप्रैल के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.1 प्रतिशत हो गई। वहीं, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.6 प्रतिशत से घटकर 6.4 प्रतिशत हुई, जो एक विरोधाभासी प्रवृत्ति को दर्शाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के रोजगार अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है, और दोनों के लिए बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, जो व्यापक श्रम बाजार तनाव की ओर इशारा करता है। यह समग्र डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती प्रस्तुत करता है।



‘भारत का इतिहास गुलामी का नहीं’

• बल्कि आक्रमणकारियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष का है - मोहन भागवत

एजेंसी**उदयपुर ।**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत का इतिहास गुलामी का नहीं, बल्कि आक्रमणकारियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष का है। भागवत ने कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध केवल महाराणा प्रताप या उनकी सेना का संघर्ष नहीं था बल्कि यह पूरे समाज के सामूहिक प्रतिरोध का प्रतीक था। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य और मुगल इतिहासकारों के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि हल्दीघाटी की विजय महाराणा प्रताप की थी। भागवत बुधवार को उदयपुर के गांधी मैदान में महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी विजय की 450वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित ‘राष्ट्र चेतना संकल्प सभा’ ??को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और

संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा और

की रक्षा के लिए संघर्ष किया।

उन्होंने कहा कि हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल साम्राज्य सेना के



गौरव के साथ मनाई जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र उन महान हस्तियों को याद रखता है, जिन्होंने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और संस्कृति

आकार, संसाधनों और शस्त्रों के मामले में श्रेष्ठ था। महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे, धन की कमी थी और उनकी सेना अपेक्षाकृत

छोटी थी, फिर भी उन्होंने संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारतीय समाज ने कभी भी आसानी से अधीनता स्वीकार नहीं की है। जब भी किसी आक्रमणकारी ने इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया, प्रतिरोध की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गई। विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को समय-समय पर एक विशिष्ट कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हल्दीघाटी के युद्ध के संदर्भ में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि मुगल इतिहासकारों के वृत्तांतों में स्वयं यह उल्लेख है कि युद्ध के दौरान मुगल सेना को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा था। यदि मुगल सेना को संघर्ष के विभिन्न चरणों में निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और युद्ध के बाद

भी वे भय और असुरक्षा की स्थिति में रहे, तो यह विचार करना आवश्यक है कि वास्तव में विजय किसकी हुई।

युद्ध की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा कि प्रारंभिक आक्रमण के दौरान मुगल सेना को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा था। दूसरे चरण में, महाराणा प्रताप की सेना के शौर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि शत्रु पक्ष के प्रमुख योद्धाओं को भारी क्षति हुई। युद्ध के तीसरे चरण के बाद, मुगल सेना की हालत ऐसी हो गई थी कि वह खुलेआम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और उसने आत्मरक्षा पर ही ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने चेतक के असाधारण साहस और युद्ध कौशल की भी प्रशंसा की।

बंगाल के बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस को झटका**मेयर अलका सेन मजूमदार ने दिया इस्तीफा**

एजेंसी बांकुड़ा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके लगने के बीच बांकुड़ा नगरनिगम की अलका सेन मजूमदार ने अचानक मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को वह बांकुड़ा जिला एसडीओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस घटना को लेकर जिले की राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं।

इस्तीफे के बाद अलका सेन मजूमदार ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों और संगठन के निर्णय का सम्मान करते हुए मेयर पद से इस्तीफा दिया है।

साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी, वह उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगी। अलका सेन

मजूमदार ने वर्ष 2022 में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नगरनिगम बोर्ड के गठन के बाद मेयर का पद संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान बांकुड़ा नगरनिगम कई बार



विवादों और राजनीतिक खींचतान के कारण चर्चा में रहा। नगरनिगम बोर्ड के भीतर मतभेद, पार्षदों की नाराजगी और प्रशासनिक फैसलों को लेकर

उठे सवालोंने कई बार संगठन और प्रशासन के सामने चुनौतियां खड़ी कीं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे समय में मेयर का इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है, जब राज्य में तृणमूल कांग्रेस को लगातार संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, अलका सेन मजूमदार ने अपने इस्तीफे को पूरी तरह व्यक्तिगत कारणों से जुड़ा बताया है, लेकिन विपक्षी दल इसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी बांकुड़ा नगरनिगम के नए मेयर के रूप में किसे जिम्मेदारी सौंपती है और क्या यह इस्तीफा केवल व्यक्तिगत कारणों तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है।

जी-7 समिट - पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज की अहम मुलाकात

व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा**एजेंसी****एवियन।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के एवियन में जी7 समिट के दौरान जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग को अधिक मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया। चांसलर मर्ज ने प्रधानमंत्री को इस साल के आखिर में जर्मनी में होने वाली 8वीं भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी बातचीत (आईजीसी) के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने व्यापार और



निवेश, रक्षा और सुरक्षा, हरित और टिकाऊ विकास, तकनीक,

इनेवेशन, शिक्षा और आवाजाही के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।

उन्होंने रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप पर हस्ताक्षर और जर्मनी से होकर गुजरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा छूट को लागू करने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इनमें पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस-यूक्रेन संघर्ष शामिल हैं। उन्होंने पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए बनी सहमति का भी स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि भारत और जर्मनी 2026 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इस साल दोनों नेताओं के बीच यह दूसरी मुलाकात है।

बदायूं में हाईवे पर ट्रैक्टरों ने ई रिक्शा सवारों को रौंदा, छह महिलाओं की मौत

निर्माणाधीन हाइवे पर रेस लगाने के दौरान हुआ हादसा, दोनों चालक फरार**एजेंसी**

बदायूं। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर को हाइवे पर रेस लगा रहे ट्रैक्टरों ने एक ई-रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ई रिक्शा सवार छह महिलाओं की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं।

घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय और एसएसपी अंकिता शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ट्रैक्टर चालकों को पकड़ लिया गया है।

जिलाधिकारी राय ने बताया कि पुलिस की जांच में यह पता चला है



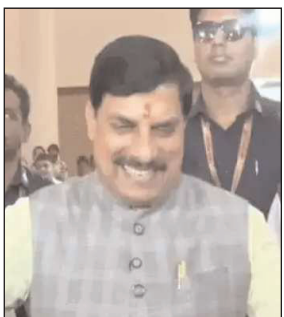
कि कछला और उझानी के बीच फूलपुर क्षेत्र में बुधवार दोपहर हाईवे पर दो ट्रैक्टर चालक रेस लगा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रैक्टरों ने एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा पर सवार महिलाएं व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने

मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा यूसीसी विधेयक : मोहन यादव

‘भगवान महाकाल ने चाहा तो विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होगा’**एजेंसी****भोपाल।**

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से यह विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों

को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू



किया जा चुका है। मध्य प्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। समान नागरिक संहिता को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें जनजातीय समुदाय अलग रहेगा। कमेटी राय ले

रही है। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल ने चाहा तो विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होगा और मध्य प्रदेश भी जल्द ही इस कानून को लागू करने वाला राज्य बन जाएगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह पांच दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेश में समान नागरिक संहिता की व्यवहारिकता जांचने और इसका मसौदा तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, कानूनी विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद् गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धपाल सिंह को शामिल किया गया है।

चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 5 करोड़ रुपये की क्रिस्टल मेथ बरामद

तस्कर पार्सल छोड़कर फरार**एजेंसी**

चेन्नई। चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग लगभग पांच करोड़ मूल्य की मेथामफेटामाइन (क्रिस्टल मेथ) की खेप जब्त की है। यह मादक पदार्थ एक लावारिस पार्सल से बरामद किया गया, जिसे विदेश भेजे जाने की योजना थी। घटना के बाद पार्सल छोड़कर फरार हुए लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, हवाई अड्डे पर नियमित जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों को एक संदिग्ध लावारिस पार्सल मिला। संदेह होने पर जब उसकी गहन जांच की गई, तो उसमें बड़ी मात्रा में क्रिस्टल मेथ छिपी हुई पाई गई। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल

और कस्टम विभाग की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ को अपने कब्जे में ले लिया और



विस्तृत जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खेप कार्गो विमान के माध्यम से मलेशिया भेजी जानी थी। मामले के खुलासे के बाद हवाई अड्डे पर यात्रियों और कार्गो सामान की जांच को और सख्त कर

दिया गया है। अधिकारियों को आशंका है कि जांच की बढ़ती सख्ती के कारण तस्कर पार्सल छोड़कर मौके से फरार

हो गए। घटना के बाद हवाई अड्डे परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों के यात्रा विवरण और अन्य दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है।

हर विधानसभा क्षेत्र में ‘तेलंगाना पब्लिक स्कूल’ खोले जाएंगे: मुख्यमंत्री रेड्डी

एजेंसी**हैदराबाद।**

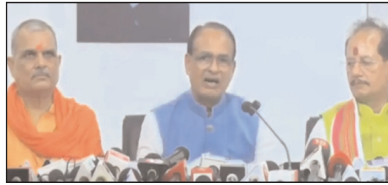
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को रंग रेड्डी जिले के अरुतला में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राज्य द्वारा संचालित ‘तेलंगाना पब्लिक स्कूल’ (टीपीएस) का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक टीपीएस स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्कूल छात्रों को खेलों का प्रशिक्षण भी देंगे ताकि भविष्य में भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हो सकें। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना का भविष्य कक्षाओं में निहित है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का भविष्य कांच से सजे महलों या रंगीन दीवारों में नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह कक्षाओं में निहित है। मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अरुतला टीपीएस को तेलंगाना के सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को समर्पित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसी भावना को राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 27 लाख छात्रों के लाभ के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने विद्यालय परिसर का दौरा कर डिजिटल कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, आधुनिक रसोई और भोजन कक्ष का निरीक्षण किया और छात्रों के साथ नाश्ता किया।

‘एक देश, एक चुनाव’, ‘स्वदेशी’ और नागरिक कर्तव्य विकसित भारत के आधारस्तंभ : शिवराज

‘आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है’**एजेंसी****पटना।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा महानगर द्वारा राजधानी पटना में आयोजित ‘प्रबुद्ध सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। सम्मेलन में उपस्थित

बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए



शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती

है। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें मंत्री या बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन वे स्वयं को हमेशा ‘कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता’ मानते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है।

अपने संबोधन में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के पुनर्जागरण और विश्वगुरु बनने का जो सपना उन्होंने देखा था, वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

एजेंसी जम्मू। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 20 और 21 जून को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा, ताकि सुरक्षा और दूसरे इंतजामों की समीक्षा की जा सके।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी समेत बड़े सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल और सीनियर ऑफिसर के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो और होम मिनিস्ट्री के सीनियर ऑफिसर भी शामिल होंगे। यह टीम 57 दिन की अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए जमीनी इंतजामों की समीक्षा करेगी, 3 जून को शुरू होगी और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षा बंधन के मौके पर संपन्न होगी। अमरनाथ यात्रा के

लिए अब तक लगभग 90 प्रतिशत सुरक्षा बलों की तैनाती की जा चुकी है, जबकि बाकी टुकड़ियां 20 जून से पहले अपनी-अपनी जगहों पर पहुंच जाएंगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यात्रा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 670 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है, जिसमें से ज्यादातर जवान कश्मीर घाटी में तैनात किए गए हैं, ताकि मल्टी-लेयर सिक्योरिटी प्रेमवर्क को मजबूत किया जा सके। अभी श्रीनगर शहर के साथ-साथ अनंतनाग और गंदरबल दोनों स्ट पर सिक्योरिटी ड्रिल की जा रही है। श्रीनगर शहर में होटलों और दुकानों की तलाशी ली जा रही है। हर आने-जाने वाले की भी तलाशी ली जा रही है। अधिकारी कई समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यात्रियों के आने और यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में लगातार बहाव के साथ अधिकारियों को इस साल भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद है।



संक्षिप्त समाचार

यूएस-ईरान समझौते के बाद होर्मुज से जल्द निकलेगे 34 भारतीय जहाज, करोड़ों किसानों को मिलेगी बड़ी राहत



तेहरान, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ला रहे भारतीय टैंकर दिशा ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर लिया है। भारत आ रहे 34 अन्य जहाजों के भी जल्द होर्मुज पार करने की उम्मीद है। ये जहाज पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज में फंसे हैं। होर्मुज में फंसे 34 जहाजों में से 16 जहाज ऐसे हैं, जो फर्टिलाइजर लेकर भारत आ रहे हैं। हालांकि अग्नी हालात सामान्य होने में वक़्त लग सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया। पश्चिम एशिया की कई अहम रिफाइनरियां और गैस प्लांट हमलों में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिससे युद्ध समाप्त होने के बाद भी आपूर्ति सामान्य होने में कई महीनों का वक़्त लग सकता है। कतर का रास लफ़फ़ान प्लांट हमले में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और वहां से ईंधन आपूर्ति सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। भारत के इस गैस प्लांट से एलपीजी आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे में हालात सामान्य होने में अभी वक़्त लगेगा।

स्विटजरलैंड हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी को तैयार

बर्न, एजेंसी, एजेंसी। स्विटजरलैंड ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का स्वागत किया है। साथ ही इसे पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही उसने इस सप्ताह के अंत में प्रस्तावित औपचारिक हस्ताक्षर समारोह की मेजबानी करने की पेशकश की है। बयान में इस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि निकट और मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा स्विटजरलैंड की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। स्विस् संघीय विदेश विभाग (एफडीएफए) ने बताया कि वह अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि इस सप्ताह के अंत में स्विटजरलैंड में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराया जा सके।

ब्रिटेन में 16 साल की उम्र से पहले बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया, प्रस्ताव से 10 में से 9 अभिभावक खुश

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में 16 साल से छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगेगा। प्रधानमंत्री की रस्टर्मी से सोमवार को इसकी घोषणा की। संबंधित नियम इस साल दिसंबर तक बन जाएंगे और 2027 मार्च- अप्रैल तक लागू होने की उम्मीद है। सरकार का तर्क है कि एल्गोरिथम आधारित प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया के उपयोग से पहले उम्र सत्यापन सख्ती से लागू होगा और नियम पालन कराने की जिम्मेदारी कंपनियों पर होगी। बैन एप में स्पंचेच, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। वॉट्सएप और सिग्नल जैसी मैसेजिंग सेवाएं फिलहाल प्रतिबंध में शामिल नहीं होंगी। ब्रिटिश सरकार के एक सर्वे में 10 में से 9 अभिभावकों ने इस प्रतिबंध का स्वागत किया है। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ द्वारा 14-24 वर्ष के युवाओं के बीच किए सर्वे के मुताबिक स्पंचेच, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम से डिप्रेशन, चिंता, अपन शरीर को लेकर हीन भावना और अकेलेपन में बढ़ोतरी होती है। अमेरिकी सर्जन जर्नल के मुताबिक रोज 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते वाले किशोरों में मानसिक समस्याओं का खतरा दोगुना होता है। अमेरिका में एक परीक्षण में पाया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बंद करने से युवाओं में खुशी, जीवन से संतुष्टि बढ़ी, डिप्रेशन-पंजाइटी में सुधार हुआ। 125 से ज्यादा देश किशोरों-बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की पहल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में साल भर पहले प्रतिबंध लागू किया गया था। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राजील में भी इस साल की शुरुआत से प्रतिबंध लागू हो चुके हैं। नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका, चीन जैसे कई देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया से जुड़े नियम सख्त किए जा रहे हैं।

ट्रंप की डील पर भड़का इजरायल, रक्षा मंत्री बोले- हम ट्रंप के गुलाम नहीं, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र

तेलअवीव, एजेंसी। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम करने और युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर सहमति बनने के बाद इजरायल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इजरायल के रक्षामंत्री इतामार बेन-निर ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में हुई डील इजरायल पर लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इजरायल अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इजरायल की तरफ से यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और अस्थायी संघर्षविराम पर शुरुआती सहमति बनने के बाद सामने आया। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार, 19 जून को स्विटजरलैंड में होगा।

अमेरिका का बी-52 बॉम्बर उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ क्रैश, हादसे में आठ लोगों की मौत

एडवर्ड्स , एजेंसी। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित मोजावे रेगिस्तान में स्थित एक वायुसेना अड्डे पर बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बमवर्षक विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान ने एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन टेकऑफ के तुरंत बाद वह दुर्घटना का शिकार हो गया। न्यूज एजेंसी एपी ने वायु सेना के हवाले से बताया कि कैलिफोर्निया के एक सैन्य अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बी-52 बमवर्षक विमान में सवार आठ लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि विमान सुबह करीब 11:20 बजे एडवर्ड्स वायुसेना अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद आपातकालीन राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए। लॉस एंजेलिस के उत्तर में स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस ने सोशल मीडिया पर कहा, "प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि इस दुर्घटना में जीवित बचना संभव नहीं था।" अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

इलाके में दिखा धुएँ का गुबार : चालक दल के सदस्यों के बारे में अभी कोई अधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, हालांकि हवाई दुर्घत्तों में विमान का मलबा लगभग पूरी तरह नष्ट दिखाई दिया। दुर्घटनाग्रस्त के बाद वायुसेना के अड्डे के एक रनवे के निकट रेगिस्तानी क्षेत्र में आग लगने से काला धुआं उठता दिखाई दिया



और आसपास कई आपातकालीन वाहन तैनात थे। सेना ने यह नहीं बताया है कि बमवर्षक विमान हथियारों से लैस था या नहीं। अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन राहत कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए एयरबेस पर गैर-व्यावसायिक आगंतुकों के प्रवेश पास अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस अमेरिकी वायुसेना के विमान परीक्षण और विकास के उत्तर में स्थित है। यह लॉस एंजेलिस से लगभग 161 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

एयरबेस पर होते हैं विमानों और हथियारों के परीक्षण : इस बेस का संचालन करने वाला 412वां टेस्ट विंग वायुसेना के सभी विमानों, हथियार प्रणालियों, सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरणों का खरीद से पहले तथा उनके पूरे सेवा काल के दौरान परीक्षण करता है। यही वह सैन्य अड्डा है जहां 1947 में वायुसेना के परीक्षण पायलट चक येगर ने

मैक 1.05 की गति हासिल कर आवाज की स्पीड को पहली बार पार किया था। विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ जेफ गुजेन्नी का मानना है कि विमान का उड़ान भरने के तुरंत बाद, बिना अधिक ऊंचाई हासिल किए दुर्घटनाग्रस्त होना किसी उड़ान नियंत्रण प्रणाली में खराबी की ओर संकेत कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उनके अनुसार, यह संभव है कि खरखराव के बाद नियंत्रण प्रणाली में कोई त्रुटि रह गई हो, इंजन में गंभीर खराबी आई हो या परीक्षण किए जा रहे किसी उपकरण में विफलता हुई हो।

बीते साल टला था एक बड़ा हादसा : एडवर्ड्स वायुसेना अड्डा एक विशाल रेगिस्तानी सैन्य ठिकाना है, जहां 1947 में चक येगर ने पहली बार ध्वनि की गति को पार किया था। यह अड्डा लॉस एंजेलिस से लगभग 100 मील (161 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है। यह दुर्घटना ऐसे समय हुई है, जब

लगभग एक वर्ष पहले जुलाई 2025 में नॉर्थ डकोटा के ऊपर उड़ान भर रहे एक क्षेत्रीय यात्री विमान के पायलट को संभावित टक्कर से बचने के लिए अचानक तेज मोड़ लेना पड़ा था। उस समय उसके उड़ान मार्ग में एक सैन्य बी-52 बमवर्षक विमान आ गया था।

बी-52 बॉम्बर क्यों है ख़ास : बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और लंबे समय से सेवा में बने हुए सामरिक बमवर्षक विमानों में से एक है। इसका विकास शीत युद्ध के दौर में किया गया था, लेकिन आधुनिक तकनीकों के समावेश के कारण यह आज भी कई देशों की वायु सेनाओं के लिए अध्ययन और रणनीतिक महत्व का विषय बना हुआ है। यह विमान लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जिससे इसे अंतरमहाद्वीपीय अभियानों में प्रभावी माना जाता है। बी-52 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भारी हथियार वहन क्षमता है। यह पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसके विशाल पंख और शक्तिशाली इंजन इसे लंबे समय तक हवा में बने रहने की क्षमता प्रदान करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह हवा में ही ईंधन भरकर अपनी उड़ान अवधि को और बढ़ा सकता है। उन्नत रडार, नेविगेशन प्रणाली और संचार उपकरणों से लैस होने के कारण यह विभिन्न मौसम परिस्थितियों में भी मिशन पूरा करने में सक्षम है।

गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 'अफगानिस्तान में रोके महिलाओं पर कार्रवाई', संयुक्त राष्ट्र का तालिबान से आग्रह

अदीस अबाबा, एजेंसी। इथियोपिया के उत्तरी अमहारा क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। ये इलाका संघर्ष से प्रभावित है और हादसे के बाद आपातकालीन सेवाओं में देरी से स्थिति और गंभीर हो गई। बता दें कि ये हादसा सोमवार की सुबह उस समय हुई जब एक खचाखच भरी बस डेल्टा क्षेत्र से राजधानी अदीस अबाबा की तरफ जा रही थी। पुलिस ने बताया कि इसी दौरान बस अचानक सड़क से फिसल गई और एक गहरी खाई में जा गिरी।

बचाव कार्य में देरी : हादसे के बाद आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया में देरी की वजह भी सामने ई है। जिस इलाके में ये हादसा हुआ, वहां बुनियादी ढांचे की भारी कमी है और एम्बुलेंस सेवाओं का भी अभाव है। यही कारण है कि घायलों को निजी वाहनों में अस्पताल ले जाना पड़ा। इस दौरान घायलों की हालत और बिगड़ने की आशंका है।

इथियोपिया में क्यों होते हैं ज्यादा

सड़क हादसे : इथियोपिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की दर काफी अधिक है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें खराब सड़क ढांचा, वाहनों की जर्जर स्थिति और यातायात नियमों का प्रभावी ढंग से पालन न होना प्रमुख हैं। देश के कई ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में सड़क नेटवर्क पर्याप्त विकसित नहीं है। संकरी और खराब सड़कों के कारण वाहन अक्सर नियंत्रण खो देते हैं और गहरी खाइयों में गिर जाते हैं। इसके अलावा, गलत तरीके से मोड़ लेना, खतरनाक ओवरटेकिंग करना, वाहनों के बीच पर्याप्त दूरी न रखना और निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाना आम समस्याएं हैं। हादसों की एक बड़ी वजह बसों और ट्रकों की खराब तकनीकी स्थिति भी है। कई वाहन क्षमता से अधिक यात्रियों या माल को डोते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। वहीं, सड़कों पर फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पैदल यात्रियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें अफगानिस्तान के तालिबान शासकों से महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को शीघ्र वापस लेने और देश में सक्रिय उन उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। इस प्रस्ताव को प्रायोजित करने वाले चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत फू कोंग ने कहा कि उम्मीद है कि अफगान सरकार मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाएगी और खुलेपन, समावेशिता तथा जिम्मेदारी की छवि पेश करेगी। प्रस्ताव के तहत अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मिशन की अवधि 17 जून 2027 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही मिशन

को बिना किसी भेदभाव के मानवीय सहायता पहुंचाने तथा राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है, जिसमें लिंग, धर्म या जातीयता के आधार पर कोई भेदभाव न हो और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, युवाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण, समान, सार्थक और सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह प्रस्ताव ऐसे समय पारित किया गया है जब इस महीने पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर में तालिबान के सफ्ट डेस कोह के कथित उल्लंघन के आरोप में कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएएमएम) के अनुसार, इन गिरफ्तारियों के विरोध में हुए एक दुर्लभ प्रदर्शन को तालिबान पुलिस ने बलपूर्वक तितर-बितर कर दिया था। इस

दौरान गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तालिबान 2021 से अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है, जब अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं की वापसी के बाद उसने सत्ता संभाली थी। इसके बाद से उसने शरीयत की कड़ी व्याख्या लागू की है, जिसके तहत महिलाओं और लड़कियों पर कई कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें प्राथमिक स्तर से भी शिक्षा और अनेक नौकरियों पर रोक शामिल है। इन नीतियों का असर अल्पसंख्यक समुदायों पर भी पड़ता है। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र मिशन को तालिबान, क्षेत्रीय देशों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच संवाद को सुगम बनाने का भी अधिकार दिया गया है। अमेरिका की उप राजदूत जेनिफर लोसेट्ट ने कहा, 'इस राजनीतिक प्रक्रिया की

सफलता के लिए तालिबान को कदम उठाने होंगे। उसे आतंकवाद-रोधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा, अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करना होगा, बंधक कूटनीति समाप्त करनी होगी और महिलाओं एवं लड़कियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन बंद करने होंगे।' पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर उन उग्रवादियों को शरण देने का आरोप लगाता रहा है, जो उसकी सीमा के भीतर घातक हमले करते हैं। हालांकि तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। फरवरी में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के भीतर किए गए हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है।

नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस के बेटे को रेप केस में 4 साल की जेल

ओस्लो, एजेंसी। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के बेटे मारियस बॉर्ग होइबो (29) को ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों में दोषी ठहराते हुए 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब मेटे-मैरिट भी दिवंगत अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से अपने पुराने संबंधों को लेकर विवादों में हैं।

अदालत ने होइबो को दो रेप मामलों में दोषी ठहराया, जबकि दो अन्य रेप आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2018 से 2024 के बीच उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया, जिनमें कुछ महिलाएं सो रही थीं या प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थीं। होइबो, क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट और क्राउन प्रिंस हाकोन के साथ शाही माहौल में बड़े हुए हैं। हालांकि, उनके पास कोई शाही उपाधि नहीं है और वे राजपरिवार की ओर से कोई आधिकारिक भूमिका नहीं निभाते। अदालत ने उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार, दूसरी साथी पर हमला, इस से जुड़े अपराध और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी दोषी पाया। होइबो ने रेप के आरोपों से इनकार किया था, लेकिन कोकीन के इस्तेमाल और मारपीट की बात स्वीकार की थी। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के बेटे मारियस बॉर्ग होइबो (29) को ओस्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों में दोषी



ठहराते हुए 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब मेटे-मैरिट भी दिवंगत अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से अपने पुराने संबंधों को लेकर विवादों में हैं। अदालत ने होइबो को दो रेप मामलों में दोषी ठहराया, जबकि दो अन्य रेप आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2018 से 2024 के बीच उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया, जिनमें कुछ महिलाएं सो रही थीं या प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थीं। होइबो, क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट और क्राउन प्रिंस हाकोन के साथ शाही माहौल में बड़े हुए हैं। हालांकि, उनके पास कोई शाही उपाधि नहीं है और वे राजपरिवार की ओर से कोई आधिकारिक भूमिका नहीं निभाते। अदालत ने उन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार, दूसरी साथी पर हमला, इस से जुड़े अपराध और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी दोषी पाया। होइबो ने रेप के आरोपों से इनकार किया था, लेकिन कोकीन के इस्तेमाल और मारपीट की बात स्वीकार की थी।